

खर के लिए कांग्रेस नहीं आउटगोइंग
असमंजस! बिहार के नतीजों पर राशि
धरुत का चौकाने वाला बयान, अपनी
पार्टी को भी दी नसीहत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राशि धरुत ने
शुक्रवार को बिहार चुनाव परिणाम की गंभीर
रूप से निराशाजनक बताया और कहा कि इस
परिणाम पर बहुत गंभीर असमंजसपूर्ण की
अवस्था है। बिहार चुनाव नतीजों में नीतीश
कुमार की एनडीए को भारी समर्थन मिला,
जिसने 198 सीटें हासिल कीं, जबकि
महागठबंधन को 39 सीटें मिलीं। भाजपा 89
सीटों के साथ राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर
उभरी है। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से चुनावी
नतीजों पर बात करते हुए धरुत ने कहा कि यह
बिल्कुल साफ है कि एनडीए को भारी बढ़त
मिल रही है। यह वाकई बेहद निराशाजनक है,
और अगर वही अंतिम नतीजे निकलते हैं।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 37

● नई दिल्ली

● शनिवार 15 नवम्बर 2025

● प्रभात कालीन

● मूल्य: 3 रूपया

● पृष्ठ: 4

सरकार के पास प्रत्येक मुद्दे से निपटने के लिए स्पष्ट नीति है : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता



नई दिल्ली। बिहार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को समस्याओं के समाधान में समय लग सकता है, लेकिन सरकार के पास प्रत्येक मुद्दे को हल करने के लिए स्पष्ट नीति और दृढ़ इरादा है। वह तेरहवें बस डिपो में स्वचालित परीक्षण स्टेशन के शिलान्यास समारोह में बोल रही थीं। गुप्ता ने कहा, "सरकार प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है। हम इलेक्ट्रिक बसें को हरी झंडी दिखा रहे हैं और इस परीक्षण केंद्र को आधारभूत बना रहे हैं। हम तालुका और नगरपालिका परीक्षण इकाई की

क्षमता बढ़ा रहे हैं। नंद नगरी में भी एक परीक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। बिजली दलों पर निगरानी माफ़ते हुए मुख्यमंत्री ने उन पर तेरे समयांतर अंतरांतर जाने का आरोप लगाया। गुप्ता ने कहा, "वे हमसे प्रत्येक पर सवाल पूछते हैं। दिल्ली में 15 साल और 11 साल तक चलने वाली सरकारों का कहना है? पिछले सरकार ने अपने कार्यकाल में 2,000 बसें खरीदीं, जबकि भाजपा सरकार ने सिर्फ आठ महीने में दिल्ली में 1,350 इलेक्ट्रिक बसें ला दी हैं। बहाल, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कुछेक के पहरों से लेकर

गुप्ता के पुनरुद्धार तक सभी मोनों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली की समस्याओं के समाधान में कुछ समय लग सकता है, लेकिन दिल्ली की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। इस बीच, गुप्ता ने शुक्रवार को तेरहवें और तुलनात्मक धर्मों का दौरा कर वहीं स्वच्छता अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि कचरा प्रबंधन निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने 'एक्स पर पोस्ट' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार प्रत्येक से निपटने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, "आज मैंने दिल्ली में चल रहे व्यापक स्वच्छता अभियान की समीक्षा के लिए तेरहवें और तुलनात्मक धर्मों का दौरा किया। मैंने प्रस्तावित कचरा संग्रहण स्थलों और स्थायी कंप्यूटर स्थलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कृषि प्रबंधन पूरी मुरादे और समयबद्ध तरीके से किया जाए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अवैतनिक लगावा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नेहरू के योगदान को नकारने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कई अन्य नेताओं ने शान्ति वन पहुंचकर नेहरू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। खरगे ने 'एक्स पर पोस्ट' किया, भारत की आजादी से लेकर एक मजबूत, आधुनिक और प्रगतिशील राष्ट्र को नींव रखने में असाधारण योगदान देने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन।



प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दूरदर्शी और निरंतर नेतृत्व से स्वतंत्र भारत में संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी और देश को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने कहा, उनके आदर्श और मूल्य आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। बिंदू के जवाहर को जयंती पर सादर नमन।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स पर पोस्ट' किया, आज उस व्यक्ति की 136वीं जयंती है जिसकी गूँज अब भी पूरी दुनिया में मुहूर्त देती है, लेकिन आधुनिक भारत के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को प्रधानमंत्री और उनकी टोली द्वारा नकारने, बदनाम करने, विवृत करने और नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की विरासत और उनकी उत्कृष्टताओं पर किए जा रहे हमले के बावजूद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। रमेश ने कहा, जो लोग 20वीं सदी के हमारे इतिहास में उन्हें मिटाने पर तुले हुए हैं, वे दासमूल अपनी ही गहरी असुरक्षाओं और द्वेषभावना को प्रकट कर रहे हैं।

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब सतर्कता निदेशालय में काम कर सकेंगे रिटायर्ड अधिकारी; जांव में आएगी तेजी

नई दिल्ली।

दिल्ली सरकार विभिन्न मामलों की जांच के लिए सतर्कता टीम को मजबूत करेगी। इसके लिए सरकार के निर्देश पर सतर्कता निदेशालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार में विभिन्न विभागों में सतर्कता मामलों से जुड़े रहे सेवा निवृत्ति अधिकारियों को नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली सरकार का सतर्कता निदेशालय सरकार से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करता है और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही मामले सीबीआई, एसीबी या अन्य एजेंसियों को जांच सौंपी जाती है। मगर पिछले एक साल से यह विभाग कम सक्रिय रहा। इसका कारण विशेषज्ञों की कमी भी बताई जा रही है। सतर्कता निदेशालय में पूर्व में रहे अधिकारियों को मानें तो लंबे समय में इस निदेशालय में विशेषज्ञों की कमी है। इसके चलते किसी भी मामले की जांच के लिए अधिकारियों और स्टाफ को रात में भी कई कई घंटे तक कार्यालय में बैठना पड़ा है। तब

जाकर जांच की रिपोर्ट वे समय से सरकार को सौंप सके। इसमें चर्चे आकर्षण घोटाला मामले में या सरकार से संबंधित या अन्य मामले में निजी सतर्कता जांच रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी रात-रात भर कार्यालय में बैठे रहे। कुछ महीने पहले ही सरकार ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि सतर्कता जांच की रिपोर्ट समय पर नहीं आ रही है। इस पर इस निदेशालय के अधिकारियों ने सरकार के सामने अपनी समस्या रखी और बताया कि विशेषज्ञों की कमी है। इसके बाद से सरकार ने इस निदेशालय को मजबूत करने की निर्देश दिए थे। जिस पर अब अमल शुरू होने की तैयारी है। इसके तहत सतर्कता निदेशालय ने विभिन्न सरकारी विभागों के सतर्कता काम में तैनात रहे उन पूर्व अधिकारियों को अपनी टीम में रखने का फैसला किया है जो पूर्व में केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार या फिर किसी अन्य सरकारी उपक्रम में रहे हैं। ऐसे विशेषज्ञों को इस निदेशालय में रखकर सतर्कता निदेशालय को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए निदेशालय से आवेदन भी मांगे हैं।

पूर्व पीएम नेहरू की 125वीं जयंती, पीएम मोदी और खरगे ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को आजादी के नायक और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हर साल 14 नवंबर को नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर देशभर में बच्चों और शिक्षकों के बीच उत्सव और यादों का माहौल रहता है। प्रधानमंत्री ने मोरारजी मीडिया मंच एक्स पर संदेश साझा करते हुए कहा, आज हम स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती मना रहे हैं। उन्हें

मेरी श्रद्धांजलि। हम स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भूमिका को याद करते हैं। नेहरू, जिन्हें बच्चों का प्रिय चाचा नेहरू कहा जाता था, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने देश को आजादी के बाद नए रास्ते दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की उनकी सोच आज भी भारत की पहचान का हिस्सा मानी जाती है। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने संसद प्रणाली को

मजबूत किया, वैज्ञानिक संस्थानों

भारत के निर्माण के लिए शिक्षा,



की नींव रखी और उद्योगों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आधुनिक

अनुसंधान और विकास को देश की प्राथमिकताओं में शामिल किया।

देश में नेहरू जी के विचारों और आदर्शों पर चर्चा तेज। उनकी 125वीं जयंती पर देशभर में एक बार फिर उनके विचारों और आदर्शों पर चर्चा तेज हुई है। इतिहासकारों का कहना है कि नेहरू का नेतृत्व वह पुल था जिसने भारत को ब्रिटिश शासन से एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनने तक का सफर तय कराया। उनकी विदेश नीति, विकास की दृष्टि और संस्थानों को मजबूत करने का प्रयास आज भी देश की नीति-निर्माण में संदर्भ बिंदु की तरह मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश बताता है कि नेहरू के

योगदान को भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आज भी सम्मान से देखा जाता है। राष्ट्र उनकी सोच और उनके द्वारा रखी गई नींव को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दोहराता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत एक शाश्वत प्रकारा स्तंभ की तरह है, जो भारत के विचार और उनके द्वारा पोषित मूल्यों - स्वतंत्रता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच - को प्रकाशित करती है। उनकी दूरदर्शिता हमारी अंतरात्मा को प्रेरित करती है।

संरक्षित वनक्षेत्रों के 1 किमी में खनन नहीं, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया रोक?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुरक्षित वनक्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों) के भीतर और ऐसे किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी खनन गतिविधि नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह टिप्पणी की कि हालांकि गैरवा फाउंडेशन मामले में गैरवा राज्य के संदर्भ में ऐसे फर्कदार पहले ही लंबे जा चुकी थी, लेकिन अब इस प्रतिबंध को पूरे भारत में लागू करने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि शीर्ष अदालत का मानना है कि संरक्षित क्षेत्रों से एक किलोमीटर की दूरी के भीतर खनन गतिविधियां वन्यजीवों के लिए हानिकारक होंगी। हालांकि गैरवा फाउंडेशन केस में ये दिशा-निर्देश केवल गैरवा राज्य के संदर्भ में जारी किए गए थे लेकिन इसे अब पूरे देश में लागू किए जाने चाहिए। हम यह आदेश देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में खनन की अनुमति नहीं होगी।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस-2025

के शुभ अवसर पर आयोजित समारोह में आप सादर आमंत्रित हैं

दिनांक: 16 नवम्बर 2025 (रविवार), समय: प्रातः 10:00 बजे, स्थान: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रायसीना रोड, नई दिल्ली

आइए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की भावना को नमन करें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के योगदान का उत्सव मनाएँ। कार्यक्रम में प्रतिष्ठित मीडिया हस्तियाँ एवं विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहेंगे।

(आयोजक)

मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन (पंजी.) एवं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया

बी.एस.चतुर्वेदी, अध्यक्ष
संपर्क: 9811063789

कोडले चन्नाप्पा, महासचिव
संपर्क: 8792496456

जगन नेगी, कोषाध्यक्ष
संपर्क: 9971770990

संयोजक: विजय कुमार भारती, चेयरमैन

CENTRAL NEWS PAPER SOCIETY OF INDIA (DELHI)

भारत में एक नए प्रकार का आतंकवाद उजगार

10 नवंबर 2025 की रात, जब देश अपने सामान्य जीवन में व्यस्त था, तब दिल्ली के इलय में स्थित लाल किले से आई एक भीषण धमाके की आवाज ने पूरे राह को हिला दिया। यह केवल एक विस्फोट नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा, उसके गौरव और उसकी सुरक्षा चेतना पर किया गया एक सुनियोजित प्रहार था।12 नवंबर 2025 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपत्तचारिक रूप से इस घटना को आतंकवादी हमला घोषित करते हुए कहा है कि यह राह की एकता, संरक्षता और सामूहिक प्रतीक पर लक्षित अतृकी घटंटा है। इस निर्णय ने न केवल इस घटना को जाननी और संवैधानिक रूप से आतंकवाद की श्रेणी में स्थिति दिया,बल्कि यह भारत की आतंकवाद - विरोधी नीति के नए अध्याय की शुरुआत का संकेत भी है।सवाल कितना केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की आजादी, स्वाधीनता और संरक्षता का जीवंत प्रतीक है। वहीं से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राह को संबोधित करते हैं। ऐसे में कां धमाका होना, अपने आप में यह स्पष्ट संकेत देता है कि आतंकी तकते अत प्रतीकवादी रूप से भारत के राष्ट्रीय अत-सम्मान पर चोट कर रहे हैं। 2000 में भी लाल किले पर हमला हुआ था, लेकिन 2025 का यह विस्फोट पहले में कहीं अधिक योजनाबद्ध तकनीकी रूप से उन्नत और क्वाइट-कोलर टैरर नेटवर्क जैसी आधुनिक एनजीनियों से जुड़ करवा

जा रहा है, 12 नवंबर को हुई आपात केबिनेट बैठक में गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त रिपोर्ट पर विचार के बाद यह निर्णय लिया गया कि लाल किले का धमाका एक "आतंकी घटना" है। यह निर्णय केवल औपचारिक घोषणा नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि विस्फोट में प्रयुक्त विस्फोटक आरड्योक्स आधारित योजनन था, जिसे डिजिटल टाइमिंग और ड्रेन लाइनियटक मिस्टम से जोड़ा गया था। तकनीकी विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि हमले के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक माइक्रो-नेटवर्क के माध्यम से विदेशी से संवाचित हुई।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी तय किया है कि इस घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी और इसके तांत वृषएए (अन्साल्फुल एक्टिविटीन प्रेवेंशन एक्ट) की धारण लागू की जाएगी। इसके अलावा, विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए और भारत के विरुद्ध आतंक के समर्थन करने वाले संगठनों पर कार्रवाई की मांग करे। साथियों बात अगर हम क्वाइट- कोलर टेररिज्म आतंकवाद का नया चेहरा इसको समझने की करें तो,लाल किले को इस घटना ने भारत में एक नए प्रकार के आतंकवाद को उगाएर किया है,क्वाइट-कोलर टेररिज्म। यह कह प्रवृति है जिसमें शिक्षित, पेशेवर और

सामाजिक रूप से सम्मानित व्यक्ति आतंक के तंत्र का हिस्सा बनते हैं। प्रारंभिक ज्ञान के अनुसार, दिल्ली और मुंबई के कुछ विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रोफेसरलस ने डेटा एंलिकेशन,डिजिटलकम्प्युनिकेशन और ज्तितीय नेनलों के माध्यम से इस नेटवर्क को सहयोग दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आतंकवाद अब केवल हथियारों या सीमापार धुमपैठ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने डिजिटल और कौटुिक मोर्चे पर भी पैर पसार लिए हैं।आतंरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौती-लाल किले पर हुआ यह विस्फोट भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को उस चुनौती को सामने लाता है जिसमें परंपरिक खतरों से आतंक बदलत है अदृश्य और तकनीकी आतंक होत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रिपर मिस्टम, और क्वाइटकोरसी से फंडिंग जैसी प्रवृतिर्यो अत भारतीय सुरक्षा संस्थाओं के लिए नई पहेली बन चुकी है। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि डिजिटल इंटेलिजेंस और ड्रेन डिफेंस नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों बात अगर हम इसघटना से अंतरराष्ट्रीय आयाम अधिक स्तर पर प्रतिक्रिया को समझने की करें तो, इस घटना के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जपान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक-नूटला नजद है। संयुक्त राह महासंजच ने कहा कि भारत पर हुआ यह हमला मान्यता के विरुद्ध अपगण है। वहीं, फेडरेशनल एक्शन

टास्क फोर्स ने इस घटना से जुड़े फंडिंग नेटवर्क की अंतरराष्ट्रीय जांच शुरू करने का संकेत दिया है।भारत अब इस मुद्दे को संयुक्त राह सुरक्षा परिषद में उठाने जा रहा है ताकि सामूहिक प्रतीकी पर आतंकी हमले को एक नई श्रेणी में शामिल किया जा सके। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहल होगी क्योंकि लाल किला जैसे विश्व परिरह स्थल पर हमला न केवल भारत पर, बल्कि मानव सभ्यता की साझा विरासत पर आधार है।अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई भूमिका- भारत लंबे समय से आतंकवाद का खिलाफ रहा है, चाहे वह 2001 का संसद हमला हो, 2008 का मुंबई हमला या पुलवामा की घासरी। लेकिन लाल किला विस्फोट एक अलग किस्म की घटना है, क्योंकि यह सांस्कृतिक अवतंकवाद का प्रतीक है,जहां उद्देश्य केवल जान-माल का नुकसान नहीं बल्कि राह की पहचान को अपमानित करना है।भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंचो पर इस नए आयाम को उठाने जा रहा है ताकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सुरक्षा के लिए मोबल प्रोटोकशन चार्टर बनाया जा सके। साथियों बात अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का पुनर्गठन इसको समझने की करें तो, केबिनेट बैठक के बाद पीएम ने स्पष्ट कहावह हमला हमारे प्रतीकों पर नहीं, हमारी आत्मा पर है। भारत हर उस जगत को नकबन देण नो हमारी संरक्षता को चुनौती देगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय आतंरिक सुरक्षा नीति 2025

में सुधार के संकेत दिए गए हैं। इसमें तीन प्रमुख बिंदुओं पर काम होगा (1) इंटेलिजेंस इंटेंशन - सभी खुफिया एजेंसियों के बीच डिजिटल क्लैटफॉर्म पर रियल-टाइम डेटा शेयरिंग। (2) माइक्रो-टैरर ट्रैकिंग यूनिट नो मोबल मोडिया, क्वािटो टाइनेशन और क्वांटैट से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगी (3) सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा बल-नो तानमल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसे राष्ट्रीय स्मारकों की हरडेक सुरक्षा के लिए गठित की जाएगी। साथियों बात अगर हमन-मन-स को प्रतिक्रिया और राजनीतिक एकनूटला को समझने की करें तो, देशभर में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश और एकता की भावना देखी गई।

विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस कदम का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म या राजनीति नहीं होती, यह मान्यता का शत्रु है। शोशल मीडिया पर देश टैग ट्रेड कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत को अब केवल 'रिप्रेटिव' नहीं बल्कि 'प्रोएक्टिव' सुरक्षा नीति अपनानी होगी। साथियों बात अगर हम जानुनी और संवैधानिक दृष्टिकोण, आर्थिक और पर्यटन पर प्रभाव को समझने की करें तो, केंद्रीय केबिनेट द्वारा इस घटना को आतंकी घोषित करने का अर्थ है कि यह अब भारतीय दंड संहिता की सामान्य धाराओं से आगे बढ़कर क्यूएए, एनआईए एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा

अधििनयम के तहत जांच और अधीयोजन के दायरे में आएगी। इसी ज्ञान एजीनियों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्ष्य संग्रह और ज्तितीय लेनदेन की निगरानी में अधिक शक्ति मिलेगी। साथ ही, यह निर्णय भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए भी एक मिसाल बनेगा कि कैसे संवैधानिक तंत्र राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में सक्षम भूमिका निभा सकता है।आर्थिक और पर्यटन पर प्रभाव-लाल किला न केवल भारत की विरासत है बल्कि दिल्ली को पर्यटन अर्थव्यवस्था का भी आधार है। इस घटना के बाद पर्यटन विभाग नेअंतरराष्ट्रीय गतिर्यो के लिए सुरक्षाआश्वासन प्रोटोकल जारी किया है।हालांकि अल्पकालिक रूप से पर्यटन पर असर पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन दीर्घकाल में सरकार ने यह भरोसा दिया है कि सुरक्षा मानकों को विश्व स्तर तक सशक्त किया जाएगा ताकि भारत को विस्मृत स्थलों की गरिमा बनी रहे। अतः अगर हम उसरोक पूरे खिरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इतिहास ने फिर टी चेनवाही,10 नवंबर 2025 की रात रात भारत के इतिहास में उस खण के रूप में दर्ज होगी जब आतंकवाद ने फिर यह दिखावा कि वह केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि दिलों और प्रतीकों पर हमला करता है। लेकिन भारत का उन्नत स्पष्ट है,इस डरे नहीं है, हम दृढ़ हैं।

सम्पादकीय...

बिहार की महिला वोट

बिहार के राजनीतिक समीकरण इनमे उलझे हुए हैं कि राजनीतिक चित्रलेखकों द्वारा इतना वैज्ञानिक विश्लेषण करना असंभव कार्य नहीं है। एक और जातिगत समीकरण है तो दूसरी तरफ उभरी-गरीबी की गहरी खाई के साथ चहुँपेरे पसरी हुई गरीबी है वहीं तीसरी तरफ स्त्री-पुरुष के बीच कार्यगत अंतर है। यह अन्तर इसका म्हा है कि बिहार से पलायन कर दूसरे प्रदेशों को गये पुरुषों की अनुपस्थिति में महिलाओं को ही घर में लेकर बाहर तक के सारे कामकाज करने होते हैं और अपनी गृहस्थी की गाड़ी को चलाना पड़ता है लेकिन एक तथ्य यह भी है कि बिहार की महिलाएं अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कार्य पारंगत मानी जाती हैं। बिहार में विगत 11 नवम्बर को हुए अंतिम चरण के दूसरे मतदान के बाद अब आज 14 नवम्बर को परिणाम आ जायेगा जिसमे सभी एंक्वाइट पोल का सच भी सामने आ जायेगा। बिहार में इस बार पिछले 75 सालों का सर्वाधिक मतदान हुआ है और अधिकतम एंक्वाइट पोल सतारुद्ध एनएच को विजय दिला रहे हैं। जबकि सम्प्रान्य तौर पर यह अवधारणा रहती है कि अधिक मतदान सतारुद्ध पार्टी के खिलाफ जाता है परन्तु बिहार में एंक्वाइट पोल ऐसा नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमन्त्री श्री नीतीश कुमार के शासन के प्रति मतदाताओं की सद्भावना रही है। वैसे यह सच है कि 2005 से नीतीश बाबू जिस पाले में भी रहे हैं नीत उसी पाले की हुई है मगर उनकी नीत के पीछे महिलाओं का समर्थन भी एक बहुत बड़ा करण माना जा रहा है। वैसे तो चुनाव आयोग ने 6 नवम्बर को पहले दौर का मतदान होने के बावजूद पुरुष व महिला मतदाताओं के अंकड़े 11 नवम्बर तक नहीं दिये मगर दूसरे दौर का अंतिम चरण 11 नवम्बर होने के बाद उसने 12 नवम्बर को महिला व पुरुष मतदाताओं के अलग-अलग अंकड़ों का मतप्रतिगत बताया जबकि कुल महिला व पुरुष मतदाताओं की संख्या अभी तक नहीं बताई है। ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है यह तो वही जाने मगर जो आंकड़े आये हैं उसके अनुसार मतदान के दोनों चरणों में कुल मतदान 66.91 प्रतिशत रहा है। जिसमें महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले 8.8 प्रतिशत अधिक मतदान किया है। राज्य में 2005 के बाद से महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान करती आ रही है मगर यह अन्तर अभी तक का सबसे बड़ा अन्तर माना जा रहा है। ऐसा स्पष्टा जाता है कि महिला मतदाताओं की पहली पसन्द श्री नीतीश कुमार होते हैं क्योंकि 2005 में पहली बार सत्ता पर बैठने के बाद उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। इसके बाद से लगातार नीतीश बाबू ही मुख्यमन्त्री बन रहे हैं और वह उनसे लिए हर बार कोई नयी योजना लाते रहते हैं। राज्य में पहले से चल रही नीतिक्ता टीवी योजना के तहत चुनाव से पहले एक करोड़ के लगभग नीतिक्ता टीवीयों को दस-दस हजार रुपये दिये गये। चुनाव पर इसका क्या असर रहा यह तो 14 नवम्बर को ही पता चलेगा परन्तु नयाँ तक मत प्रतिगत का सवाल है तो इस बार के चुनावों में महिलाओं में यह 71.6 प्रतिशत रहा जबकि पुरुषों में यह 62.8 प्रतिशत रहा। इस अन्तर को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के चुनाव में पुरुषों के मुकाबले विरायों ने पाँच लाख अधिक वोट डाले। ये आंकड़े तब हैं जबकि राज्य में दूनु विरोध गहन मतदाता पुनर्विषण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम अधिक वोट। बिहार में 3.93 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 3.51 करोड़ महिला मतदाता हैं। इस प्रकार पुरुष व महिला मतदाताओं में 42.34 लाख मतों का अन्तर है। हालाँकि चुनाव आयोग ने इन चुनावों में कुल स्त्री व पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या जारी नहीं की है मगर प्रतिप्रसता के आधार पर तो आंकड़ा निकलता है वह 2.52 करोड़ महिला वोटरों का है और 2.47 करोड़ पुरुष वोटरों का है। नैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है। इसी जाहज होता है कि महिला वोटरों में ज्यादा उत्सख था। यह उत्सख इसीलिए था कि बिहार में महिलाओं के मिर पर जिम्मेदारी का बोझ पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहता है लेकिन क्या इसका मतलब यह निकाल लिया जाये कि महिलाओं के सभी वोट नीतीश बाबू को पड़े हैं? यह अहकलन सही नहीं होगा क्योंकि एक तरफ यह भी कहा जाता है कि बिहार का समाज विविध जातिगत खांचों में बंटा हुआ है। अगर यह सच है तो इसका असर महिला मतदाताओं पर भी पड़ना चाहिए क्योंकि राज्य में सभी चुनाव विश्लेषण जातिगत आधार पर ही किये जाते हैं। यह भी सच है कि अलग-अलग जातियों की अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं। यदि महिलाएं जाति-पाति से ऊपर उठकर मतदान करती हैं तो इसे बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग कहा जायेगा परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं क्योंकि चुनाव नतीजे हमें इसका प्रमाण नहीं देते रहे हैं। यदि पुरुष इतिहास देखें तो वे प्रमाण तो हैं कि नीतीश बाबू फरवदे में रहे है मगर इस बात के समुत् नहीं है कि महिलाओं ने जात-पात से ऊपर उठकर मतदान किया है। अभी तक 2010 में नीतीश बाबू की जद (एन) पार्टी को सर्वाधिक 115 सीटें हमिल हुई थीं। इन चुनावों में महिलाओं ने 54.49 प्रतिशत व पुरुषों ने 51.12 प्रतिशत वोट खले। इन चुनावों में भाजपा व जद (यू) का गठबन्धन था। यह वोट 2005 से 2010 तक के नीतीश के कार्यकाल के आधार पर था जिसमें लालू जी की पार्टी को मात्र 22 सीटों पर ही सन्तोष करना पड़ा था। इसके बाद 2015 में नीतीश बाबू का लालू जी से गठजोड़ था जिसमें महिलाओं ने 60.48 प्रतिशत व पुरुषों ने 53.32 प्रतिशत मत दिया था। इसमें लालू जी की पार्टी को सर्वाधिक 80 व नीतीश बाबू की पार्टी को 71 सीटें ही मिली थीं। अतः इन चुनावों में जातिगत समीकरण ने भी अपना काम किया था। इस बार 2025 में यही देखा जना है कि महिलाओं का अधिक मत प्रतिगत किम हद तक नीतीश बाबू की मदद करता है।

बिहार विधानसभा चुनाव

2025 के जनादेश के मायने

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने राज्य की राजनीति और सामाजिक समीकरणों पर बड़ा प्रभाव डाला है। इस बार बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड सीटों के साथ भारी बहुमत से सत्ता में लौट रहा है, जबकि महागठबंधन (राजद-कांग्रेस गठबंधन) को गंभीर झटका लगा है। चुनाव परिणाम के निष्कर्ष से स्पष्ट है कि एनडीए ने 243 में से 200 से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित की है, जिसमें बीजेपी को 91, जेडीयू को 81 एवं लोक जनशक्ति पार्टी (राजविकास) की 21 सीटें मिली हैं। वहीं, विपक्षी महागठबंधन महज 38 सीटों पर सिमट गया है, जिसमें राजद 26, कांग्रेस 4 और नामदल (सीपीआई, सीपीएम आदि) 6 सीटों पर आगे दिखे। ये आंकड़े अन्तिम हैं। इसमें मामूली बदलाव सम्भाव्य है। मतदाता प्रतिशत 66.91प्रॉसेंट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, महिलाएं 71.6प्रॉसेंट की हिस्सेदारी के साथ निर्णायक भूमिका में रहीं। इन नतीजों के मायने दिलसप्त है-

पहला, शासन और नेतृत्व पर असर- चुनाव परिणाम ने इन्क इनन की सरकार यानी केंद्र-राज्य एक ही साझा गठबंधन के पारंप्रयुते पर जस्ता की मुहर को मजबूती दी है। इससे राज्य में स्थिरता, नीति निरंतरता तथा केंद्र से सहयोग की उम्मीद है। एनडीए में बीजेपी की सीट्स जेडीयू से अधिक हैं, जिससे भाजपा का राज्य के सत्ता-समीकरण, गतिमंडल गठन और नीतियों पर बड़ा प्रभाव होगा।

दूसरा, विश्व के लिए संदेश- राजद और महागठबंधन की हार, सामकरी युवा व महिला वोटर्स के बड़ी संख्या में एनडीए की ओर जाने

का कारण हुई है, जिससे विश्वोत्थ वृत्तियों को खुद की रणनीति और नेतृत्व की समीक्षा करनी होगी। तीसरा, सामाजिक-राजनीतिक पटल पर प्रभाव- एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड सीटों के साथ का रुझान, सामाजिक विकास, शिक्षा-स्वास्थ्य, सुरक्षा के मुद्दों को आगे लाता है; वहीं जाति-आधारित राजनीति कुछ हद तक कमजोर होती दिखी। वहीं, छोटे दलों की भूमिका खमीर रही है, जिससे स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रों के लिए कैलिब्रिंग एक्ट की आवश्यकता बढ़ गई है।

चतुर्थ, राष्ट्रीय राजनीति के लिए संकेत- बिहार का परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनोबल और संदेश देता है कि क्षेत्रीय गठबंधन नीति और विकास एजेंडा कारगर है। वहीं, एक संकल यह भी है कि बिहार परिणाम का राष्ट्रीय राजनीति पर असर क्या होगा? तो जवाब होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की भारी जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर कई स्तरों पर असर पड़ेगा। बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन की सफलता विश्वो्थ दलों, विशेष रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पारंप्रयुते करती है, जबकि एनडीए की नीतियों और नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलती है। राष्ट्रीय राजनीति का नया समीकरण-एनडीए की जीत से प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व का लोक-प्रियता को बड़ा सहारा मिला है। इससे भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव 2029 और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में रहेगी। बिहार के नतीजे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एनडीए के लिए

गति और उद्वारण बनेंगे। वहीं, विश्वो्थ इंडिया गठबंधन में अंदरूनी फूट, नेतृत्व संकट और जमीनी कमजोरियाँ उजागर हुई हैं। कमजोर प्रदर्शन से विपक्षी गठबंधन के भविष्य, नेतृत्व और संयुक्त रणनीति को लेकर गंभीर सवाल पैदा होंगे।

साथ ही, मसला बनचौं (य. बंगाल), अखिलेश वादव (यूपी) जैसे क्षेत्रीय नेताओं के लिए भी बिहार का परिणाम मार्गदर्शक होगा कि उन्हें अपनी गठबंधन संरचना पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। नीतिगत और सामाजिक प्रभाव-बिहार में एनडीए की सरकार के विकास-कार्य, स्वास्थ-शिक्षा और महिला-सशक्तिकरण एजेंडा राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राथमिकता पा सकता है। वहीं, महिलाओं और युवाओं के बड़े हिस्से का समर्थन एनडीए को मिला, इससे सामाजिक सुधार और चुनावी रणनीति में इन वर्गों का महत्व बढ़ेगा। वहीं, भाजपा और जेडीयू में सीटों के समीकरण से भी केंद्रीय सत्ता में गठबंधन के आतंरिक समीकरण बल सकते हैं, सामकरी मोदी सरकार 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका बढ़ सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव पर असर- बिहार परिणाम ने भाजपा को 2029 चुनाव के लिए मनोबल, रणनीति और समर्थन का ठेसा आधार दिया है। विपक्षी गठबंधन को फिर से खुद को संगठित और प्रामाजिक साबित करने की चुनौतियाँ मिली हैं। बिहार जैसे राज्य का चुनाव परिणाम राष्ट्रीय राजनीति को दिशा, गठबंधन व्यवस्था और चुनावी मुद्दों को गहराई से प्रभावित करता है। 2025 के नतीजे छह को केंद्र में मजबूती व विश्व को नए सिरे से आत्मगर्भन का संकेत देते हैं।

आतंकियों का मक़सद - देशवासियों में भाईचाराक सांझ तोड़ना

कुछ सालों पहले तक जितने भी खिलाड़ी मले ही किसी भी खेल से हों अपने रिस्की स्वरूप के साथ ही खेलते हुए देश को अनेक पदक जीतकर दिए। मगर अचानक फैशन प्रस्ती की एक ऐसी हवा वली जिसने सिख युवाओं के दिलों दिमाग पर रिस्की स्वरूप से छेड़छाड़ का वलन पैठ कर दिया और आम सिख से लेकर, बड़े व्यवसायी, खिलाड़ी, फौजी कोई भी इसरो बच नहीं पाए। सबसे अधिक नुकसान रिस्की को पंजाबी फिल्में और पंजाबी सिंगरों ने पहुंचाया। सिख युवा इन्हें ही अपना रोल माडल समझकर इनके जैसे दिखने के चक्कर में रिस्की स्वरूप का त्याग करने लगे। जिसके परिणाम स्वरूप आज बहुत ही कम युवा ऐसे बचे हैं जो आज भी पूर्ण रिस्की स्वरूप में रहकर केवल देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर देश, कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं में एक हैं विक्रमवीर सिंह बावा जिसने अपने पूरे रिस्की स्वरूप के साथ वीर से आव्रतन गैन का खिताब हासिल किया है। विक्रम वीर सिंह श्री गुरु अंगद देव जी की 16वीं पीढ़ी से हैं। उनसे पहले बावा दास जी, शिरोमणि पंथ अकाली बुद्ध दल के पहले मुख्ी जयदेवर बाबा विनोद सिंह जी, और 15वीं पीढ़ी के बावा गुरिंदर सिंह जो कि अनेक धार्मिक जयदेवियों से जुड़े हुए हैं।

आतंकवाद का कोई भी धर्म या मजबूत नहीं होता और ना ही इनके दिलों में मान्यता होती है, इनका मकसद केवल समान में आतंक पैदा कर अपने निजी स्वार्थों को पूर्ति करना होता है। पिछले लंबे समय से भारत का पड़ोसी मुक्त पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकियों को समर्थन देकर उनका इस्तेमाल भारत में आतंक का माहौल बनाने के लिए करता है। पाकिस्तान की हमेशा सभा रहती है कि भारत में आपसी प्रेम और भाईचारा सझ को तोड़ नाए जिसके लिए वह अक्सर मुस्लिम और सिख भाईचारे के बेरोनगार और जगतजर्म युवाओं को धर्म की आस्था के नाम पर या फिर पैसे का लालच देकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करता है और युवा वर्ग जिसे पूर्ण धर्म के प्रति ज्ञान का अपभाव रहता है वह जल्द ही इनके स्वप्ने में फंस जाते हैं। देखा जाए तो कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि बिना वजह किसी का खून बहला जाए, आतंक पैदा किया जाये। हल ही में दिल्ली के लाल किला के पास जहाँ हमेशा पीछपड रहती है वहाँ विस्फोट किया गया जिससे स्पष्ट है कि आतंकियों ने केवल आतंक पैदा करने की दृष्टि से ऐसा किया और यह भी हो सकता है कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी स्ताब्दी समारण के पास जहाँ लाल किला में होने वाले हैं जिनकी रैवारियाँ लगातार जागे हैं और देश के प्रधानमंत्री, गुरु मंत्रों से लेकर कई ब्रिटिश और राजनीतिक शास्त्रसर्तों के साथ-साथ देश-विदेश से लाखों को गिनती में श्रद्धालुगण भाग लेने वाले हैं। मगर सावद आतंकी संगठनों को यह समागम नाशुकरावार है। वह नहीं चाहते कि हिंदू-सिख भाईचारा मिलकर है और इस काम में खलिस्तानी संगठनों के द्वारा भी कई तरह की ख्याजिर्त रवी जा रही हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है जहाँ एक ओर इन्हें लाल किला के पास हुए धमाके पर दुःख प्रकट कर रहा है वहीं खलिस्तानी संगठनों के नुमाइंद बेसुकी बयानबानी करते नुज्देनो है जिससे पता चलता है कि उसकी मानवीयता मिट चुकी है, वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी नीचा तक उतर सकते हैं। खलिस्तानी संगठनों के प्रतिनिधि इस घटना को 1984 के सिख विरोधी हत्याकांड से जुड़ेनो को कीर्तिशर कर रहे हैं जिसमें हजारों सिखों का एक पार्टी विशेष के द्वारा सुनिर्गोपन तरीके से कल्लेआम किया था। मौजूदा समय में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर दिल्ली सिद्ध गुरुद्वार प्रत्येक कमेटो सहित अन्य सिख संस्थाओं को सहयोग

से प्रेम रखता है तो इन गुरुद्वारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रसरखल को बेहतर बनाए चला अपनी पीढ़ीों से बाबन आए। सिखी स्वरूप में आयतन गैन बनकर ग्रीस में भारत का झण्डा कुर्द किया आज के समय में देखने को मिलता है किसी मुसलम बड़े पूर्ववने से पहले ही लोग अपने सिखी स्वरूप की तिलांजलि दे देते हैं क्योंकि ज्यादातर युवाओं को यह लगता है कि सिखी स्वरूप कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत में रुकावट पैदा कर सकता है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिखी स्वरूप में रहते हुए ही सिख यैमिकों के द्वारा अनेक युद्धों में किसी भी हमिल को। यहाँ तक कि अंजीनी हकूमत के समय में सिख सैनिक अपनी सिखी वेशभूषा में ही रहते थे। कुछ सालों पहले तक जितने भी हिस्साई भन्ने ही किसी भी खेल से हों अपने सिखी स्वरूप के साथ ही खेलते हुए देश को अनेक पदक जीतकर दिए। मगर अचानक फैशन प्रस्ती की एक ऐसी हवा ज्सी जिसने सिख युवाओं के दिलों दिमाग पर सिखी स्वरूप से छेड़छाड़ का चलन पैठ कर दिया और आम सिख से लेकर, बड़े व्यवसायी, खिलाड़ी, फौजी कोई भी इससे बच नहीं पाए। सबसे अधिक नुकसान सिखों को पंजाबी फिल्में और पंजाबी सिंगरों ने पहुंचाया। सिख युवा इन्हें ही अपना रोल माडल समझकर इनके जैसे दिखने के चक्कर में सिखी स्वरूप का त्याग करने लगे। जिसके परिणाम स्वरूप आज बहुत ही कम युवा ऐसे बचे हैं जो आज भी पूर्ण सिखी स्वरूप में रहकर केवल देश ही नहीं विदेशों में भी जाकर देश, कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हीं में एक हैं विक्रमवीर सिंह बाबा जिसमें अपने पूरे सिखी स्वरूप के साथ ग्रीस में आयतन गैन का खिताब हासिल किया है। विक्रम वीर सिंह श्री गुरु अंगद देव जी की 16वीं पीढ़ी से हैं। उनसे पहले बाबा दास जी, शिरोमणि पंथ अकाली बुद्ध दल के पहले मुख्ी जयदेवर बाबा विनोद सिंह जी, और 15वीं पीढ़ी के बाबा गुरिंदर सिंह जो कि अनेक धार्मिक जयदेवियों से जुड़े हुए हैं। तख्त पटना साहिब कमेटो सदस्य, एवं चीफ खालसा दीवान महाराष्ट्र के प्रथम गुरिंदर सिंह बाबा के पूरे परिवार का गुरुद्वार में येवा मे नुज्देव एवं सिखी चक्रा की समर्पित होने का परिणाम ही है कि परिवार के युवा भी अपने पुर्वजों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए देश, धर्म और समाज का नाम रोशन करते आ रहे हैं। सिम तक विक्रम वीर सिंह बाबा ने वह खिताब जीता, उस समय जयकारी को गून से माहौल देखने योग्य था।

बहराइच में आज से नवजात शिशु देखभाल सप्ताह शुरू

बहराइच।

जिले में नवजात शिशुओं की मृत्यु, विशेषकर जन्म के पहले सात दिनों में होने वाली नवजात मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से 15 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान समय से पूर्व जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की विशेष देखभाल सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही समुदाय को नवजात की सुरक्षित और वैज्ञानिक देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय कुमार ने बताया कि प्रदेश में नवजात मृत्यु दर में सुधार दर्ज हुआ है। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम- 2023 के अनुसार, प्रदेश की नवजात मृत्यु दर 26 प्रति 1,000 जीवित जन्म रही, जो वर्ष 2022 में 27 थी। जिले में नवजात मृत्यु दर को घटाने के लिए संस्थान आधारित नवजात देखभाल और समुदाय आधारित नवजात देखभाल कार्यक्रम पूर्व से ही संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा



कि नवजात शिशु की देखभाल अत्यंत संवेदनशील होती है, इसलिए आवश्यक है सभी प्रसव अस्पताल में कराए जाए और प्रसव के बाद माँ व शिशु को कम से कम 48 घंटे तक चिकित्सालय में ही रुके। जन्म के तुरंत बाद शिशु को नहलाने के बजाय पॉल्डर साफ कपड़े पहनाए और पहले घंटे में माँ का गाढ़ा पीला दूध अवश्य पिलाया जाए। छह महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाए और शिशु को आवश्यक सभी टीके अवश्य लगाए जाए। उन्होंने कहा कि समय से पहले जन्मे या कम वजन

वाले बच्चों के लिए कंगारू मदर केयर विधि एक बेहतर उपाय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवजात को मसाज, घुट्टे, शहद या अन्य घरेलू पदार्थ देना नुकसानदायक है और इनसे पूरी तरह परहेज किया जाए। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी नृजेश सिंह ने बताया कि नवजात शिशु देखभाल सप्ताह, समुदाय को सही जानकारी देने का एक प्रभावी माध्यम होगा। उन्होंने कहा कि जिले में आशा, एएनएम और स्वास्थ्य टीम घर-घर जाकर परिवारों को यह समझाएंगी कि

21 नवंबर तक चलेगा

अभियान,

- समुदाय में बढ़ेगा जन्म

के बाद देखभाल का

संदेश

शून्य नवजात मृत्यु के

लक्ष्य की ओर बड़ा कदम

जन्म के तुरंत बाद साफ-सुथरा वातावरण, माँ का पहला दूध, कंगारू मदर केयर और शिशु की नियमित निगरानी, बीमारियों और जोखिमों से बचाव में सहायक होती है। उन्होंने कहा नवजात देखभाल केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि इसमें परिवार और समुदाय की सहभागिता भी आवश्यक रहेगी। जब परिवार जागरूक होंगे, तभी नवजात को सुरक्षित जीवन का मजबूत आधार मिलेगा।

देश मोदी के साथ था, है और आगे भी रहेगा-हरीश द्विवेदी

बस्ती (उप)

। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए असम राज्य के प्रभारी एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के पक्ष में अपना बेहद स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया है। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस चुनाव में मुकाबला विश्वास और खोखले वादों के बीच था, और बिहार की जनता ने एक बार फिर विश्वास की राह चुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा आज भी अटूट और अटल है। यही विश्वास देश को आगे बढ़ा रहा है और यही भरोसा विरोधियों की राजनीति को बार-बार नकारात्मक करता है। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एक बार फिर 'रिजेक्टेड नेता' साबित हुए हैं। जनता झुठ और भ्रम की राजनीति को अब कतई स्वीकार करने वाली



नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के भविष्य का फैसला जनता ने आज ही कर दिया है। विकास, स्थिरता और सुशासन के आगे झुठ, नकारात्मकता और खोखले वादों की कोई जगह नहीं है। अपने बयान के अंत में श्री द्विवेदी ने कहा देश मोदी जी के साथ था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि भारत में हमेशा विश्वास ही जीतता है।

जून तक बढ़ाई जाये एसआईआर फार्म जमा करने की तिथि



मुरादाबाद।

इनवायरमेंट प्रोक्टेक्शन मूवमेंट मुरादाबाद की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को सम्बोधित ज्ञापन एडीएम सिटी मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत चल रहे एसआईआर के फार्म बीएलओ के जमा करने तिथि असुविधा को देखते हुए 4 दिसम्बर से 30 जून

2026तक करने की मांग की है। एसआईआर आनलाइन आवेदन की तकनीकी समस्या का समाधान व बीएलओ को उचित सुविधाएं दिलाने व सरकारी स्वयं सेवी संस्थाएं का सहयोग देने कि मांग की ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले में सय्यद जुनैर अली, तनजीम शास्त्री, अभय कुमार सिंह एडवोकेट, अरशद परवेज एडवोकेट, आवरण अग्रवाल एडवोकेट, रोहित सिंह एडवोकेट तारिक आदि मौजूद रहे।

बिहार में प्रचंड जीत से भाजपाई उत्साहित, मनाया जश्न

मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वाधान में महानगर अध्यक्ष गिरिश भंडूला के नेतृत्व में महानगर कार्यालय बुद्धि बिहार पर बिहार प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली प्रचंड जीत की खुशी में खेल नगाड़ों की थाप पर नाच गाकर खुशी मनाई इस प्रचण्ड जीत की सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मनाई। महानगर अध्यक्ष गिरिश भंडूला जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल एवं सभी ने ने पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल का लड्डू खिलाकर इस प्रचण्ड जीत की बधाई दी एवं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ी जीत हुई है। महानगर अध्यक्ष गिरिश भंडूला ने कहा कि बिहार प्रदेश में इस प्रचण्ड जीत ने साबित कर दिया कि भाजपा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सर्व समाज को साथ लेकर कार्य कर रही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा पूर्णतया सफल हो रहा है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, महानगर अध्यक्ष गिरिश भंडूला, जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल, क्षेत्रीय मीडिया सहप्रभारी निमित्त जयसवाल, महानगर मीडिया प्रभारी राजीव गुप्ता, दिनेश



शीर्षवाल, नवदीप टंडन, विशाल त्यागी, हेमराज सैनी, राहुल शर्मा, सुनीता शर्मा, शशी किरण, अभिषेक चौबे, विशाल रस्तोगी, विपिन प्रजापति, सोमपाल प्रजापति, मनमोहन सैनी, किशन लाल जाटव, दीक्षांत चौधरी, अश्विनी शर्मा सौरभ सक्सेना हरिओम सैनी विशाल कुमार आदि शामिल रहे।

रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर विदुषी महिला का होगा सम्मान

मुरादाबाद। रानी लक्ष्मी बाई जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एक बैठक दिव्य सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद में की गई रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर एक विदुषी महिला को सम्मानित भी किया जाएगा। संयोजन समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में देश हित में सभी धर्म के छात्राओं को रानी लक्ष्मी बाई जयंती के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में विस्तार से बताया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रदीप शर्मा ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अल्प आयु में देश हित में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना देश भक्ति एवं त्याग बलिदान और अपने देश के सामाज को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ प्रदीप शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष विमलेंद्र विमल, महानगर अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा, डीपी सिंह आदि उपस्थित रहे।

आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में न बरतें लापरवाही : डीएम

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अनुसार सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ने आईजीआरएस, फैमली आईडी, उद्यान, आईसीडीएस, कन्या सुमंगला योजना, छानवृत्ति योजना, दुग्ध विकास, पशुपालन, औद्योगिक विकास, विद्युत, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, प्रोजेक्ट अलंकार और ऑपरेशन कायाकल्प सहित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में विभागवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को सक्रियता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त/प्रभारी



अधिकारी आईजीआरएस को दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों की आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण के सापेक्ष संतुष्टि 80 प्रतिशत से कम है उन सभी अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की जाए साथ ही उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही, निस्तारण की गुणवत्ता का ध्यान न रखने तथा शिकायतकर्ता से संपर्क न करने की वजह से जिले की रैंक प्रभावित हो रही है। जनपद में संचालित गौशालाओं में ठंड के दौरान सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए

रखने के संबंध में उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गौशाला में बने शेड ठंढे होने चाहिए ताकि गौवंश को ठंड से बचाव में मदद मिले। उन्होंने नोडल अधिकारियों के भ्रमण की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और कहा कि पशुओं के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए तथा नोडल अधिकारियों के भ्रमण के दौरान पाई गई कमियों को दुरुस्त करने में भी सक्रियता बरती जाए। गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी

जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर मासिक समीक्षा बैठक

लाने के निर्देश दिए तथा कहा कि सीसीटीवी कैमरे संचालित होने के उपरांत गौशालाओं की स्थिति की जिले स्तर से सीधे तौर पर मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालयों में बाल मैत्री शीचालयों के निर्माण कार्य को भी गति दी जाए साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप विद्यालयों के संतुष्टिकरण को लेकर भी गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम, अपर जिलाधिकारी नगर 'योति सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण मौजूद रहे।

ब्रह्माकुमारीज गोरखपुर में आयोजित हुआ सहज योगी जीवन विषयक कार्यक्रम

गोरखपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित सहज योगी जीवन विषयक कार्यक्रम का आयोजन मोहरीपुर स्थिति संस्था की मुख्य शाखा में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नई दिल्ली से पदार्थ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याती प्राप्त वक्ता एवं जी.बी. पंत अस्पताल, नई दिल्ली के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर बी. के. डॉ मोहित गुप्ता ने सभी उपस्थित श्रोताओं से सहज राजयोग के विषय पर वृत्तीय जानकारी अपने जीवन के निज अनुभवों के उदाहरण के साथ, सरल भाषा में साझा किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन कर एवं ईश्वरीय स्मृति के गीतों के साथ हुआ। ब्रह्माकुमारीज मोहरीपुर की प्रभारी बी. के. पुष्पा दीदी सिसवां बाजार की प्रभार बी. के. मनोज दीदी शाहपुर प्रभारी बी. के. पारुल दीदी एवं अन्य बहनों ने मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बी.के. डॉ मोहित गुप्ता ने सहज राजयोग से सहज योगी जीवन जीने की कला सिखाते हुए सभी श्रोताओं को बताया की कैसे मन की शक्ति के द्वारा जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों को सहज ही पार किया जा सकता है। जटिल से जटिल बीमारियों को उचित चिकित्सा के साथ मन की शक्ति के द्वारा, राजयोग के अभ्यास एवं प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। डॉ मोहित ने अपने जीवन के उदाहरणों से सभी श्रोताओं को प्रेरित किया एवं सकारात्मक विचार तथा राजयोग के अभ्यास के सकारात्मक प्रभाव को सभी के मध्य प्रस्तुत किया। कुलपति डॉ पूनम टण्डन ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु ब्रह्माकुमारीज गोरखपुर को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा ब्रह्माकुमारीज संस्था द्वारा समाज में दिये जा रहे नैतिक शिक्षा एवं मानव मूल्यों के कार्यों की सराहना की।



बाल दिवस पर रेल विभाग ने कराई प्रतियोगिताएं, बच्चों को बांटे उपहार

मुरादाबाद।

बाल दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन मुरादाबाद मंडल की अध्यक्ष सुमन मोर्य की उपस्थिति में रेलवे ऑफिसर्स क्लब में रंगारंग कार्यक्रमों

का आयोजन किया गया। बाल विद्या मंदिर, निकट रेलवे स्टेशन पर, मुरादाबाद के छोटे-छोटे बच्चों द्वारा कार्यक्रम में मंच से अनेक सांस्कृतिक एवं देश भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उत्तर रेलवे

महिला कल्याण संगठन मुरादाबाद मंडल की अध्यक्ष सुमन मोर्य तथा उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, मुरादाबाद मंडल की उपस्थित अन्य पदाधिकारी सुशीला गौतम, मौनिका एवं साक्षी गुप्ता, स्कूल ईंचार्ज बाल विद्या मंदिर स्कूल, इन्द्रजीत

कोर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेल चिकित्सालय सहित बाल विद्या मंदिर स्कूल स्टाफ ने तालियों के साथ बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहा। उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, द्वारा पूर्व में स्कूल बच्चों के लिए मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर

, चंदौसी स्टेशनों पर स्कूलों में आयोजित की गयी निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग/पेंटिंग प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को आज बाल दिवस के अवसर पर उत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन, मुरादाबाद मंडल की अध्यक्ष सुमन

मौर्य द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संगठन द्वारा बच्चों को स्कूल ड्रेस एवं गिफ्ट पैक का वितरण भी किया गया। उत्तर रेलवे स्काउट्स एवं गाइड्स, मुरादाबाद मंडल की टीम कार्यक्रम में उपस्थित रही।

जा रही रफ्तार की जानकारी सुनते ही
शाहीन ने जवाहरलाल नेहरू की
तलाशें इंडियन ने नेहरू का लो
कतों में घाटकों की और अन्य लोक
भी इसमें शामिल किया। इसमें तब
का मौलवी इस्लामिक भी शामिल
नहीं जम्मू-कश्मीर पुलिस की हथिय
है और अलग फलाना में उसके किस्म
फॉर्मर का इस्तेमाल भी नियमित
सम्बन्धों के लिए किया गया था।

स्तर पर एक उल्लेखनीय बदलाव दर्शाती है, जो दर्शाता है कि मतदाता एक बार फिर उनके सामने मोहन लाल विष्णम बता रहे हैं। एक आधुनिक समाज में भरे, समर्पित भाषा-जट (यु) गठन का जो वासी ने इस बार चुनावों रणभूमि को काफी हद तक स्वयं दिया है। पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रथममंत्री मोदी के नीतीश कुमार के साथ पत्रकारों से खुदे स्टैंड-से, गठबंधन में एक अनुष्ठान और पुनर्जात मोदी पत्र दिया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढाँचे के निस्सार, सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक स्थितियों पर जोर दिया गया।

राजनैतिक सहमति और जन-
विश्वास, दोनों को परीक्षा के तहत
देखा जा रहा है। बिहार को अ
जेल एज कहे जाने वाले सा
बाहर निकालने के लिए
मुशासन बानू कहे जाये
मुख्यमंत्री को हल के वष
मतदाताओं को थकान और
बदलेते राजनैतिक समीकरण
सबलों का सामना करना पड़े
इसके बावजूद, मौजूद स्थान ज

गठबंधन की वापसी ने इस चुनावों रणभूमि को काफी हद तक स्थिर कर दिया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कुमर के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं, गठबंधन ने एक एकमुट्ठ पुनर्जाति मोर्चा पेश किया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया।